

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03052024-254021
SG-DL-E-03052024-254021असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2024/वैशाख 12, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 39
No. 30]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 12, 1946	[N. C. T. D. No. 39

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मई, 2024

सं. 38 /नियम/दि.उ.न्या.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 (1917 का अधिनियम 4) की धारा 3 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के माननीय उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवम् आदेश, खंड-4, अध्याय-16 के भाग एफ (ए) में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करता है:

संशोधन

निम्नलिखित को दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवम् आदेश, खंड-4, अध्याय-16

के भाग-एफ (ए) के मौजूदा नियम 1 के तुरंत बाद नियम 1-ए, 1-बी और 1-सी के रूप में शामिल किया जाएगा:

“1-ए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए अभिलेखों का नाशकरण- इन नियमों में निर्धारित संरक्षण की किसी भी अवधि के बावजूद, कोई भी न्यायिक अभिलेख, पुस्तक या कागज़ को, इसके बाद अपवादित मामलों को छोड़कर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 7 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाने के बाद नष्ट किया जा सकता है।

बशर्ते कि इसमें कुछ भी निम्नलिखित दस्तावेज़ों पर लागू नहीं होगा:

क्रमांक	दस्तावेज़ों का विवरण
1.	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 13 में परिभाषित परक्राम्य लिखत (चेक के अलावा)
2.	मुखतारनामा अधिनियम, 1882 (1882 का 7) की धारा 1-ए में परिभाषित मुखतारनामा
3.	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 3 में परिभाषित कोई न्यास
4.	किसी भी नाम से ज्ञात किसी अन्य वसीयतनामे को शामिल करते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित कोई वसीयतनामा।
5.	अचल संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण या ऐसी संपत्ति में किसी भी हित हेतु कोई संविदा

बशर्ते यह भी कि इन नियमों के अनुसार जिन दस्तावेज़ों को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में संरक्षित किए जाने के बावजूद भौतिक रूप में संरक्षित किया जाना जारी रहेगा।

1-बी नष्ट करने से पहले अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने का पर्यवेक्षण- न्यायिक अभिलेखों, पुस्तकों या कागज़ातों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने का काम, उनके नष्ट होने से पहले, नियम 1-ए के अनुसार, जैसा भी आवश्यक हो, समय-समय पर किया जाएगा और उसका पर्यवेक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे इस प्रयोजन के लिए संबंधित ज़िले के प्रधान ज़िला एवम् सत्र न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाए, और अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा। इसे एक ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भविष्य में उस तक पहुंच के लिए पूर्ण समर्थन के साथ डिजिटल संरक्षण के लिए उपयुक्त हो और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छेड़छाड़ संरक्षित वातावरण में रखा जाएगा।

1-सी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रतिधारण- ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को संबंधित ज़िले के अभिलेख कक्ष के साथ-साथ दिल्ली के अन्य न्यायालय परिसरों के एक दूसरे ज़िले के अभिलेख कक्ष में और भारत के किसी दूरदराज़ के शहर में स्थित सर्वर पर भी रखा जाएगा, जैसा कि समय-समय पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाए।

अपवाद- निम्नलिखित न्यायिक अभिलेखों, पुस्तक या कागज़ को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारित नहीं किया जाएगा:-

- ऐसे अभिलेख जिन्हें उच्च न्यायालय नियम एवम् आदेश, खंड-4, अध्याय-16 के भाग एफ (ए) के नियम 7 के अनुसार स्थायी रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता होती है।
- महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों से संबंधित अभिलेख।
- शासकीय गुप्त बात अधिनियम या भारत संघ की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित अभिलेख या ऐसे मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा गोपनीय घोषित किया गया अभिलेख।
- कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति, सावधि जमा रसीद और समान प्रकृति का दस्तावेज़।

स्पष्टीकरण-I : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 7 के अनुसार, जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि दस्तावेज़ों, अभिलेखों या सूचना को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित किया जाए, वहां ऐसी उपेक्षा पूर्ण कर दी समझी जाएगी यदि ऐसे दस्तावेज़, अभिलेखों या सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारित किया जाता है।

स्पष्टीकरण-II : किसी भी मूल अभिलेख को नष्ट करने से पहले, सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति, जो नियमों के अनुसार ऐसे दस्तावेज़ को पुनः प्राप्त करने का हकदार हो, उसे वापस करने के लिए ऐसा कोई अनुरोध कर सके।

स्पष्टीकरण-III : जब किसी दस्तावेज़ को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारित किया जाता है और ऐसा दस्तावेज़ स्वयं एक प्रति है और मूल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तन के समय इस तथ्य का उल्लेख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में ही स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।”

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,
कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd May, 2024

No. 38/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Section 3 of the Destruction of Records Act, 1917 (4 of 1917) & Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in Part – F (A) of Chapter 16 of Volume IV of Delhi High Court Rules & Orders : -

AMENDMENTS

THE FOLLOWING SHALL BE INSERTED AS RULES 1A, 1B AND 1C IMMEDIATELY AFTER THE EXISTING RULE 1 OF PART-F (A) OF CHAPTER 16 OF VOLUME IV OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-

“1A **Destruction of Records retained in electronic form** - Notwithstanding any period of preservation prescribed in these Rules, any judicial record, book or paper, except in the cases hereinafter excepted, may be destroyed after being retained in electronic form, in accordance with section 7 of the Information Technology Act, 2000.

Provided that nothing in this rule shall apply to the following documents:-

Sr. No.	Description of documents
1.	A negotiable instrument (other than a cheque) as defined in Section 13 of the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881).
2.	A power-of-attorney as defined in Section 1A of the Powers-of-Attorney Act, 1882 (7 of 1882).
3.	A trust as defined in Section 3 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882).
4.	A Will as defined in clause (h) of Section 2 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) including any other testamentary disposition by whatever name called.
5.	Any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such Property.

Provided further that documents which are to be preserved permanently as per these rules shall continue to be preserved in physical form notwithstanding their preservation in electronic form.

1B Supervision of conversion of record into electronic form before destruction – The conversion of judicial records, books, or papers, in electronic form, shall be carried out from time to time, before their destruction, in accordance with Rule 1A, as may be necessary and shall be supervised by such officer as may be appointed by the Principal District & Sessions Judge of concerned district for the purpose, and authenticated by affixing his or her digital signatures. It shall be retained in a format which is suitable for digital preservation with full support for future access and such electronic record be kept in temper-proof environment.

1C Retention of electronic record - Such electronic record would be kept in the Record Room of concerned District as well as in the Record Room of one another District of different court complex of Delhi and also at Server situated in a remote city of India as may be decided by High Court of Delhi from time to time.

Exceptions : Following judicial records, book or paper, would not be retained in electronic form :-

- Records which are required to be preserved in perpetuity as per Rule 7, Part-F (A) of Chapter-16 of Volume-IV of High Court Rules & Orders.
- Record pertaining to all matters related to sexual assault on woman.
- Record pertaining to any matter related to Official Secrets Act or any matter related to sovereignty and integrity of Union of India or declared confidential by the court which tried such matter.

- d) Any Valuable Security, Fixed Deposit Receipt and document of similar nature.

Explanation-I : According to section 7 of the Information Technology Act, 2000, where any law provides that documents, records or information shall be retained for any specific period, then, that requirement shall be deemed to have been satisfied if such document, records or information are retained in the electronic form.

Explanation-II : Before destruction of any original record, notice be issued to all concerned to enable any person, entitled to reclaim such document as per Rules, to make any such request for return of the same.

Explanation-III : When any document is retained in electronic form and such document itself is a copy and not original, such fact be clearly mentioned in the electronic record itself at the time of conversion in electronic form.”

NOTE: THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,
KANWAL JEET ARORA, Registrar General